Graft in Services and Public Life

217. **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Kotla Venkaiah:
Shri M. N. Swamy:
Shri Laxmi Dass:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 225 on the 3rd March, 1965 and state:

(a) whether any new and effective method has been devised in consultation with the team of U.S. experts who came in December, 1964 on the invitation of Government of India for effectively dealing with graft in services and public life; and

(b) if so, the broad outline thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). Three officers from U.S.A. came in November and December, 1964. One of them came to advise on Police Administration and his Report is not concerned with the general problem of corruption in Services and public life. The Report of the Officer who came to advise on the legal aspects of investigation and prosecution received recently is under consideration. The report of the officer who came to advise on Reform of Personnel Administration, has not yet been received.

हिन्दी-भाषी राज्यों से पत्र-व्यवहार

218. **श्री किन्नर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहकार समिति की हिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिये गठित उप-समिति ने अपनी हाल की बैठक में सरकार से मांग की है और उन्हें एक ज्ञापन एवं संकल्प भेजा है जिसमें कहा है कि केन्द्र द्वारा हिन्दी भाषी राज्यों से पत्र-व्यवहार करते समय हिन्दी में लिखे गये पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भेजना अनिवार्य नहीं होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां । परन्तु यह ज्ञापन और संकल्प हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक प्रतिनिधिमंडल के नेता की हैसियत से संसद सदस्य श्री सेठ गोविंद दास द्वारा प्रधान मंत्री के सामने पेश किये गये थे ।

(ख) मुख्य मंत्रियों के 13 अगस्त, 1964 के सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि यदि कोई राज्य केन्द्र को हिन्दी में पत्र भेजता है, तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिये । इस निर्णय का आधार वर्तमान स्थिति को व्यवहारिक रूप में स्वीकार करना है । वास्तविक स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अधिकांश भाग को हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान नहीं है ।

Council of Kerala University

219. Shri Mohammed Koya: Will Minister of **Education** be pleased state:

(a) whether Government have received any memorandum from Calicut Municipal Corporation asking for representation for the Council in the University Senate;

(b) whether Government are aware that representation is given to all Municipalities and Calicut Corporation; and

(c) whether Government propose to amend the University of Kerala Act to avoid this anomaly?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. However, a resolution adopted by the Corporation of Calicut requesting that a suitable provision may be made in the Kerala University Act, 1957, to enable the Council to elect its repre-